



2026:AHC:124912

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 19184 वर्ष 2026

बोलाआवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : मानवेन्द्र सिंह

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मनवेन्द्र सिंह और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री जी.पी. सिंह की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- यह जमानत याचिका मामले संख्या 374/2025 में धारा 85, 105 बीएनएस के तहत, पुलिस स्टेशन खागा, जिला फतेहपुर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि एफआईआर के अनुसार, आवेदक ने अपनी पत्नी पर हमला किया था, जिसकी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के सिर पर एक खरोंच का निशान पाया गया है और दूसरी चोट शरीर के गैर-महत्वपूर्ण हिस्सों पर पाई गई है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि आवेदक ने पुलिस के सामने स्वीकार किया है कि घटना वाले दिन उसके और उसकी पत्नी के बीच कुछ कहासुनी हुई थी और गुस्से में आकर उसने कोई कठोर और कुंद वस्तु उसकी पीठ पर फेंकी, हालांकि, वह वस्तु उसके सिर के पिछले हिस्से पर लगी। इसके

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक की ओर से मृत्यु का कारण बनने का कोई इरादा नहीं माना जा सकता है। आवेदक 15.9.2025 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. *इसके विपरीत*, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि मृतक को मृत्यु पूर्व सिर में चोट लगी थी और उसकी मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व चोट ही पाई गई है।

5. एफआईआर के अनुसार, आवेदक ने मृतक के सिर के पिछले हिस्से पर किसी कठोर और कुंद वस्तु से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसके सिर पर एक चोट और शरीर के गैर-महत्वपूर्ण हिस्सों पर छह चोटें आईं। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मृत्यु का कारण मृत्यु से पहले सिर में लगी चोट के कारण कोमा बताया गया है। आवेदक ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया है कि गुस्से में आकर उसने मृतक के सिर के पिछले हिस्से पर कोई कठोर और कुंद वस्तु फेंकी, हालांकि वह वस्तु उसके सिर के पिछले हिस्से पर लगी।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 6765) मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. तदनुसार, यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. उपर्युक्त अपराध में अभियोक्ता **बोला** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा। आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल कोर्ट जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

12. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, **पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन री: सुओ मोटू रिट पिटीशन (क्रिमिनल) नंबर 4 ऑफ 2021 दिनांक 31.01.2023 (2024) 10 एससीसी 685** में प्रकाशित आदेश के अनुसार, कार्यालय को **संबंधित जेल अधीक्षक** के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के जरिए आवेदक को इस आदेश की एक प्रति 24 घंटे के भीतर भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

3 जून, 2026

मधुरिमा

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।